LOK SABHA

Monday, December 16, 1963/Agrahayana 25, 1885 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

Mr. Speaker: Secretary may call out the names of the Members who have come to make and subscribe the oath or affirmation under the Constitution and then the Minister of Parliamentary Affairs may introduce the Members to the House.

Secretary: Shri Mukunda Padmanaba Shinkre.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I have great pleasure in introducing to you and through you to the House Shri Mukunda Padmanaba Shinkre who has been returned to Lok Sabha from Marmagoa constituency of Goa, Daman and Diu.

Shri Mukunda Padmanaba Shinkre (Marmogoa).

Secretary: Shri Peter Augustus Alvares.

(Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I have great pleasure in introducing to you and through you to the House Shri Peter Augustus Alvares who has been returned to Lok Sabha from Panjim constituency of Goa, Daman and Diu.

Shri Peter Augustus Alvares (Panjim).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गाजियाबाद के किसान

*५७६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री २६ अगस्त १६६३ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के आस पास औद्योगिक बस्ती के लिए अर्जित भूमि के लिए किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे की दर अन्तिम रूप से तय हो गई है ;

(ख) इन सम्बन्धित किसानों ने अपने जो सुझाव प्रधान मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किए थे तथा उन के कहने पर प्रश्न की जांच करने के बाद कृषि मंत्री द्वारा जो सुझाव दिये गये थे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) राज्य सरकार ने निजी उद्योगियों को उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान देने के हेतु गाजियाबाद के पास भूमि ली थी, न कि औद्योगिक बस्ती के लिए । उक्त सरकार ६ फरवरी, १६६२ की बाजार दरों पर मुआवजा देने के लिये राजी हो गई है ।

(ख) और (ग). भूमि, कुंओं, नल-कूपों और बागों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की सुविधायें देने के विषय में किसानों और केन्द्रीय कृषि मंत्री के सुझावों में से ज्यादातर राज्य सरकार ने मान लिए हैं ।